

[श्री महेश्वर सिंह]

हो गए, उपजाऊ भूमि बह गई, सड़कें टूट गयीं, पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं सारी नष्ट हो गयीं। विशेषकर चंबा, कुल्हू, उन्ना और किन्नौर जिलों में तो तबाही मच गई। अभी तक की सूचना के अनुसार 120 लोगों की जानें गयीं, 980 पशु मर गए और 6,941 से भी अधिक घर गिर गए हैं।

महोदय, 11 कुल्हू के कुल्हू में एक साठ नामक गांव में ही बाढ़ल फटने से अकेले 27 लोगों की मृत्यु उसी घटना-स्थल पर हो गई और 2 महिलाएं व्यास नदी में बह गयीं। ठीक एक मास के बाद पुनः उसी कुल्हू जिले के फोजल नामक स्थान पर फिर बाढ़ल फटा और 11 लोगों की जानें उसी घटना-स्थल पर चली गयीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि प्रभावित व्यक्तियों को वहां की सरकार समय पर समुचित राहत पहुंचाने में असफल रही है। उसका एक कारण यह भी है कि हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट में डूबा है और हिमाचल प्रदेश जैसे प्रदेश के लिए, जो कि केन्द्र पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर है, समुचित राहत राशि प्रदान करना कठिन हो नहीं बल्कि असंभव है। दूसरी और प्रधानमंत्री महोदय ने यह चेष्टा की है कि जो लोग मर गए हैं, उनके आश्रितों को 50,000/- रुपये प्रति मृतक प्रदान की जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर कुल मृतक संख्या देखी जाए तो 120 लोग मरे हैं और अभी तक जो राहत राशि यहां से गयी है वह केवल 42 लाख रुपये हैं। अब अगर इसके 50 हजार के हिसाब से बाँटे तो यह भी पर्याप्त नहीं है। इसलिए मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश को अधिक धनराशि प्रदान की जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां तक 9वें वित्त आयोग का संबंध है, उसकी सिफारिशों से पूर्व यह प्रथा थी कि जब भी इस प्रकार का कोई प्राकृतिक प्रकोप होता था, तो केन्द्र से एक जांच दल जाता था, उसकी सिफारिशों पर ही संबंधित प्रदेश को धनराशि प्रदान की जाती थी राहत कार्यों के लिए, लेकिन जब से 9वें वित्त आयोग की सिफारिश आई है हिमाचल जैसे प्रदेश और बाकी पहाड़ी प्रदेश, जो कि केन्द्र पर आर्थिक सहायता के लिए निर्भर है, उनके लिए एक समस्या उत्पन्न हो गयी है। उनके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि वह जो नई प्रथा चली है, इसको समाप्त किया जाए। उदाहरणतः हिमाचल प्रदेश को आज कुल मिलाकर उसकी जनसंख्या के आधार पर 18 करोड़ रुपये दिया जाता है और वह भी उस शर्त पर दिया

जाता है कि उसका एक चौथाई, अर्थात् साढ़े चार करोड़ का प्रावधान हिमाचल सरकार को करना पड़ता है। तभी वार्षिक धन जो वहां से आता है वह 18 करोड़ के लगभग बैठता है। आप स्वयं अनुमान लगाएं कि जहां बाढ़ करोड़ों से ऊपर नुकसान हो गया है वहां यह 18 करोड़ रुपया क्या करेगा? इसलिए मैं मांग करना चाहूंगा कि इस प्रकार की राहत को बंद किया जाए और जो सही मायनों में वहां नुकसान हुआ है, उसके आधार पर राहत प्रदान की जाए।

दूसरा, महोदय, जो आज रिवेन्यू रिलीफ मेन्यूअल है, उसके अंतर्गत राहत देने के भी विभिन्न प्रांतों में विभिन्न मापदंड हैं। उदाहरणतः हिमाचल प्रदेश में अगर 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति मर जाए, चाहे उसकी उम्र 17 वर्ष 11 महीने की हो, तो केवल साढ़े छः हजार रुपया दिया जाता है और अगर 18 वर्ष से ऊपर की आयु हो तो पच्चीस हजार दिया जा रहा है। तो मैं यह भी आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहूंगा कि सारे देश के लिए समान कानून बने और जो रिवेन्यू रिलीफ मेन्यूअल है वह सारे देश के लिए समान होना चाहिए ताकि एक तरह की राहत सब लोगों को मिले।

आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

Relief and rehabilitation for flood-affected people of Bihar

श्री जलालुद्दीन अंसारी (बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में अभी हाल में नदियों में बाढ़ आ जाने से बिहार के बड़े हिस्से में आम जनता का जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है, मकान भी गिरे हैं, फसल बर्बाद हो गई है, कुछ गांवों का कटाव हुआ है, उनके पुनर्वास का सवाल है। वहां की सरकार सहायता भी कर सकती है, कर रही है लेकिन इस विपत्ति में जो राहत कार्य, बचाव कार्य और सहायता के जो साधन उपलब्ध करए जाने चाहिए, उसके लिए बिहार सरकार के पास साधन नहीं हैं। मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि अपवाद को छोड़कर बिहार के उत्तरी हिस्से में प्रतिवर्ष बाढ़ आती है और बिहार के दक्षिणी हिस्से में आम तौर पर सूखा रहता है। यह निर्यात बन गई है बिहार की कि एक बड़ा हिस्सा, उत्तरी बिहार, बाढ़ से पीड़ित है और दक्षिणी बिहार सूखे से पीड़ित है। आप जानते हैं कि बिहार में नदियों की कमी नहीं है। गंगा में बाढ़ आ जाती है, सोन नदी में बाढ़ आ जाती है, पुनपुन, गंडक, कोसी इन तमाम नदियों का जल-स्तार जब ऊपर आ जाता है तो बिहार जल-मग्न हो जाता है। उस समय जन-जीवन कितना कष्टकर हो जाता है, इसका अंदाजा

اور راجیہ سرکار جو وہاں رہی ہے
 اُن سے مانگ کرتے رہے ہیں کہ
 بہار کو سوکھے اور باڑھ سے چھٹکارا
 دلانے کے لئے باڑھ نیتوں سے سنبھالی
 پری یوجنائیں بنائی جائیں۔ بہار
 نے اس کے لئے کیندریہ سرکار کا بھی
 برابر دھیان آکر شت کیا کہ باڑھ
 نیتوں سے سنبھالی پری یوجنائیں اگر بنا
 دی جائیں۔ ندیوں کو باندھ دیا جائے۔
 اُن سے نہریں نکالی جائیں۔ رزروائر
 بنادئے جائیں۔ تو سنبھالی کے استھانی
 پر بندھ ہو جائیں گے۔ اور سوکھا
 ختم ہو جائے گا۔ رزروائر بنا
 دینے سے اور ندیوں کو باندھ دینے
 سے یہ جو باڑھ کی وبھیشکا آتی ہے۔
 اس سے استھانی چھٹکارا ہو جائے گا۔
 لیکن بہار جیسے پردیش کسے
 طرف آزادی کے ۷۷ سالوں میں
 کیندریہ سرکار نے دھیان نہیں دیا۔
 نہ پورو ورتی سرکاروں نے دھیان
 دیا اور پورا بہار باڑھ اور سوکھے
 کی وبھیشکا سے جو جھتا رہتا ہے اور
 وہاں کاجیون است و است رستا
 ہے۔ اس لئے میرا سچاؤ ہے کہ تنکال
 کیندریہ سرکار باڑھ سے پھڑتوں کو
 راحت مہیا کرنے کے لئے اور اُن

نے جینز و اس کے لئے اور مولیشنوں کیلئے
 چارے کا پر بندھ کرنے کے لئے آوشیک
 مدد بہار سرکار کو دے۔
 میرا دوسرا سچھاؤ یہ ہے کہ جیسی
 کہ میں نے ابھی چرچا کی کہ بہار کو باڑھ اور
 سوکھے سے ملتی مل سکے اور بہار اُن
 ویتوں سے ملکت ہو کر خوش حال بن سکے
 اس کے لئے باڑھ نیتوں ایونم سنبھالی
 یوجنا کا خاکہ بن کر پڑا ہوا ہے۔ اس
 پر عمل کر کے پیئے۔ ہمارا جو پڑوسی دلش
 ہے نیپال۔ اس سے بھی کئی بار رائے
 صلاح لی گئی ہے۔ لیکن اس کو کارینوت
 کرنے کے لئے کیندریہ سرکار کو جو دھیان
 دینا چاہئے وہ نہیں دیا گیا۔ میرا انورودھ
 ہے کہ اس اور کیندریہ سرکار
 دھیان دے۔

یہ چند باتیں باڑھ سے استپن استھانی
 کے سمبندھ میں اور اس سے چھٹکارا پانے
 کے سمبندھ میں میں نے آپ کے سامنے
 رکھی ہیں۔ میں آشا کرتا ہوں کہ سرکار
 اس پر وجار کر کے کچھ ٹھوس قدم اٹھائے
 گی۔ تاکہ بہار کو ہر سال جو اس ویتی کو
 کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس سے ملکتے
 مل سکے۔

”ختم شد“

श्री नरेन्द्र चाहल: महोदय, केन्द्र सरकार की तरफ से फरक्का डैम योजना प्रस्तावित है और इसके लिए किसानों को उनकी भूमि के मुआवजे का चुगतान भी हो गया है। स्थानीय निदान के लिए अगर फरक्का डैम योजना चालू कर दी जाए केन्द्र सरकार द्वारा तो बहुत बड़ा हल बाढ़ समस्या का हो सकता है बिहार के लिए। इसी की साथ में जल्लाहीन अंसारी जी के साथ अपने को सम्बद्ध करता हूँ।

Undue delay In releasing quota for medical students of North-Eastern region

DR. B.B. DUTTA (Nominated): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the "House to a serious malady that seems to afflict our Union Health Ministry. Because of that, it is also affecting the fate of a good number of students who have been selected for admission into various medical colleges.

Mr. Vice-Chairman, as you are aware, in our country the States which have not got a medical institution of their own within their jurisdiction are allotted a certain number of seats elsewhere every year by a quota system and it is the Union Health Ministry which releases the quota. But it has become a disease that every year the release of the quota is delayed, inordinately delayed. This year, till the last Friday, when I came back from my place, till then, they had not got the quota. The students have appeared for tests and interviews. They have been selected. They have also been told that 'they are going in for the medical line, they have to abandon the engineering and other lines and they cannot apply for the other lines. If they have been selected for the other lines then they have to forego their chance. When ultimately the quota is released, some of the students from those backward, sensitive, areas go to the principal of the medical institution concerned who says, "You are too late to report to the institution. The classes have started. You cannot cope with it. So go back." In this way, every year, some seats get lost. Already the seats these States get are much less than the requirement. There is a lot of frustration, quarrel, over seat allotment. On top of all that, this delay is creating a lot of problems. Another thing is, corruption creeps in. When these institutions do not

fill the seats from the quota, what do they do? They sell the seats to other people. They deny seats to the rightful candidates on the plea that they have come late and sell the seats to some other people.

So, Mr. Vice-Chairman, my earnest appeal is this. Let a communication from this House go to the Union Health Ministry to the effect that the quota for this year should be promptly released tomorrow itself and henceforth, the delay should not recur. This delay is avoidable. It is a matter of simple administration. They can do it very well in time. It should not recur.

Secondly, they should seriously consider increasing the number of seats for these backward States.

We should not play with the career of our boys and girls. We have already got a lot of problems in those areas. So, kindly take note of this point, Mr. Vice-Chairman.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Mr Vice-Chairman, while associating myself with what Dr. Dutta has said, I want to say something. Fifty per cent of the seats are reserved for all-India students. There is a fraud, as Mr. Dutta has rightly pointed out and this fraud is there in my State also. Some people are kept on the waiting list. If the Central students do not come, these seats should go to those students. These students in combination contribute something. But the people in Delhi delay the allocation of seats. I think there should be some investigation into the inordinate delay so much so that the deserving students are not deprived of the seats. I very much agree with my hon. colleague. I demand that an inquiry should be conducted as to why there is such an inordinate delay of three to four months.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Minister, would you like to respond? If you are interested, you may respond.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI PABAN SINGH GHATOWAR): Sir, I share the